1 सितम्बर 2018 को इन्दौर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के लांच के अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

_____

1. यह बहुत हर्ष का विषय है कि आज देश भर में पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का शुभारंभ हो रहा है। यह योजना वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) की दिशा में एक बहुत बड़ा एवं नया कदम है। पोस्ट आफिस का नेटवर्क सुदूर गांवों तक है एवं बहुत remote areas में भी वे लोगों को उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

2. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूरे भारत में 650 केन्द्रों पर एक साथ IPPB का लांच दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से करेंगे। यह ऐसी योजना है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं बायोमैट्रिक डाटा का उपयोग करते हुए बचत खाता खोला जाएगा। इसमें multilingual support system रहेगा जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को भी उनकी अपनी भाषा में आसानी से बैंकिंग के नियम व प्रक्रिया समझने में आसानी होगी।

3. यह योजना वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव सिद्ध होगी। पोस्ट विभाग द्वारा जो QR Card जारी किया जाएगा उसमें बायोमैट्रिक्स के माध्यम से आप अपने एकाउंट्स से पैसा भेज सकते हैं, निकाल

सकते हैं। इससे बैंक के सारे काम बिना कोई नम्बर याद किए हो जाएंगे और Biometric होने के कारण यह सुरक्षित भी होगा। इसके लिए एक टॉल फ्री नं. भी जारी हुआ है जिस पर या फिर अपने निकटतम पोस्ट–आफिस में जाकर आप इंडिया पोस्ट पेमैंट्स बैंक के विषय में अपनी समस्याओं के बारे में समाधान जान सकते हैं।

4. हमारे देश में बचत करने की प्रवृत्ति हमेशा से रही है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाता है। इस योजना के प्रारंभ होने से गांव–गांव में स्त्री–पुरुष, युवक–युवतियां पोस्ट आफिस में IPPB के माध्यम से अपनी छोटी–छोटी बचत को आसानी से विभिन्न स्कीमों में जमा कर पाएंगे। इसका लाभ शहरों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। इसमें जमा राशि पर बैंक की तुलना में अधिक दर पर ब्याज प्राप्त होगा। साथ ही, कुल लाभ का 25 प्रतिशत डाक विभाग के कर्मचारियों में वितरित होगा।

5. भारत में डाकघरों का बहुत विस्तृत जाल है। नियोजित विकास प्रक्रिया ने ही भारतीय डाक को दुनिया की सबसे बड़ी एवं बेहतरीन डाक सेवा प्रणाली बनाया है। भारत में लगभग एक लाख पचपन हजार पोस्ट आफिस हैं और अपने उद्देश्य ''Service before Help'' को अक्षरशः चरितार्थ करते हैं। Post Office Savings Banks ने भारतीय विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

6. IPPB का सूत्र वाक्य हैः– "No customer is too small, no transaction too insignificant, and no deposit too little." (इसका अर्थ है कि प्रत्येक ग्राहक का महत्व है, सभी लेन–देन महत्वपूर्ण हैं और कोई जमा राशि छोटी नहीं होती।) इसका उद्देश्य ग्राहक के रूप में आम आदमी को most accessible, affordable and trusted banking facility प्रदान करना है।

7. बैंक एवं दूसरी वित्तीय संस्थाओं की तुलना में पोस्ट आफिस बहुत कम कीमत पर सुगमता से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देते हैं। अब तो उन क्षेत्रों, जिन्हें सामान्य पोस्ट आफिस कवर नहीं कर पाते, उनको कवर करने के लिए मोबाइल पोस्ट आफिस भी हमारे समक्ष है। वर्तमान में डाकघरों में लगभग 17 करोड़ बचत खाते हैं और उम्मीद है अब इस संख्या में बहुत बढ़ोत्तरी होगी।

8. पोस्टमैन से आम आदमी का विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक नाता है। उन्हें सभी का स्नेह एवं विश्वास हासिल होता है एवं उनकी कर्त्तव्यपरायणता, श्रमशीलता, जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के बारे में हम सभी भलीभांति परिचित हैं। उनको जो सम्मान मिलता है, उसके पीछे उनका बरसों का कठिन श्रम एवं समर्पित सेवा निहित है। वास्तव में, वे आम आदमी के जीवन के सुख–दुःख के सहभागी होते हैं। मुझे उम्मीद है कि तीन लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक इस आईपीपीबी सेवा को बहुत सुगम एवं सरल बनाएंगे। इस नई योजना के शुरू होने के बाद यह सामाजिक–सांस्कृतिक संबंध और सुदृढ़ होगा

क्योंकि अब पोस्टमैन संचार व्यवस्था से आगे बढ़कर सामाजिक–आर्थिक बदलाव के अग्रदूत बनते हुए अब आम जनता के बीच वित्तीय सलाहकार की नई भूमिका के रूप में होंगे।

9. अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से युक्त डाक सेवक, आधार से जुड़े खाताधारकों को ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा, धन को अर्जन करने की सुविधा एवं वित्तीय साक्षरता प्रदान करेंगे। वे सिर्फ पत्र और मनीऑर्डर लाने–ले जाने तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि अपने साथ लाई गई QR CARD की मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं की छोटी–छोटी धनराशि जमा करने की सहुलियत भी उन्हें दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त, पोस्ट आफिस की कई योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, आर.डी. योजना, मनी बैक पॉलिसी, जिनकी किस्तों को जमा करने के लिए भी लोगों को डाकखाने नही जाना होगा। ये सब सेवाएं अब पोस्टमैन के द्वारा आसानी से घर पर ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। इससे यकीनन बचत के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा।

10. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। आर्थिक वृद्धि नई उंचाईयों पर जा रही है, पर सरकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि विकास का फल गरीबों तक पहुंचे। Financial inclusion यानि समाज के कमज़ोर, वंचित व निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवा के दायरे में लाना आजकल सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है।

महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान का सपना भी तो इसी से जुड़ा है।

11. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन अब धीरे–धीरे विकास का पर्याय बन रहा है। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में भी डाकघर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है।

12. विभिन्न शोधों से यह पता चला है कि किसी भी देश की प्रगति के लिए गरीबों और वंचित वर्ग का वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) बुनियादी आवश्यकता है और भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहां पर पारम्परिक वित्तीय व्यवस्थाएं जैसे महाजनी, साहूकारी व्यवस्था, गांवों में आपस में विश्वास आधारित लेन–देन, क्रेडिट सोसाइटी, कमेटी इत्यादि सुव्यवस्थापित हैं, वहां पर गरीबों और वंचितों के शोषण और सरकारी योजनाओं और सब्सिडी में भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। साथ ही, ये प्रक्रियाएं formal economy का हिस्सा नहीं होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था को उनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी जन–धन योजना की शुरूआत की जिसने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। जन–धन योजना के तहत अब तक लगभग 32.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लेकिन देश के कुछ भाग और जनता अभी भी formal economy का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। आज के इस पहल से उन लोगों के Financial Inclusion का वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

13. हम विकसित देशों की प्रगति का अध्ययन एवं आकलन करें तो यह पता चलेगा कि वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) से अर्जित आत्मविश्वास और लाभ ही गरीब जनता की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दृष्टि से इस स्कीम का हिस्सा बनने वाले लोगों के लिए और देश के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से विशेषकर, गांव के वृद्ध व्यक्ति, महिलाएं, खेतिहर मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा।

14. IPPB की पहुंच सुदूर गांवों, छोटे शहरों, कस्बों एवं remote areas तक होगी। इसके दो फायदे होंगे। एक तो गरीब लोगों का बचत का पैसा जो घरों में रहता है, वह इसके माध्यम से जमा होगा, तो उससे उनके पैसे की सुरक्षा तो होगी ही, साथ ही इससे उस धन का उपयोग अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया जा सकेगा। निष्क्रिय धन का एक बेहतर वित्तीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल निश्चय ही एक revolutionary idea कहा जा सकता है।

15. यह हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में विद्या और धन का क्या महत्व है। विपत्ति की अवस्था में धन का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित हैः–

''पुस्तकस्था तु या विद्या, परहस्तगतं च धनम्।

कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम्।।''

(किताब में रखी विद्या व दूसरे के हाथों में गया हुआ धन कभी भी जरूरत के समय काम नहीं आते।)

26. अर्थात्, विद्या, धर्म और धन का संचय सभी नागरिकों को ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार बूंद–बूंद पानी से घड़ा भरता है। क्योंकि यही राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के लोगों एवं राष्ट्रहित में IPPB का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ अत्यन्त लाभकारी एवं दूरगामी परिणाम देने वाला सिद्ध होगा।

धन्यवाद।

————